

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11861/2024

- पायल सोनी पुत्री श्री चित्ररंजन सोनी, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी
109, सूर्य नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।
- प्रियंका पुत्री श्री राजेश कुमार, आयु लगभग 22 वर्ष, ग्राम व डाकघर
खेड़ी बुरा, तहसील और जिला चरखी दादरी, हरियाणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से, नई
बिल्डिंग, डांगियावास बाईपास, जोधपुर, राजस्थान-342001।
- रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, नई बिल्डिंग, डांगियावास
बाईपास, जोधपुर, राजस्थान- 342001।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए

:

श्री आशीष शर्मा उपाध्याय,

श्री जयकिशन सिंह और

श्री रामप्रकाश शर्मा

प्रतिवादी के लिए

:

श्री ए.के. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता की

ओर से श्री विष्णु कांत शर्मा

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

23/07/2024

1. सुना गया।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करेंगे कि यद्यपि

याचिकाकर्ताओं ने ओएमआर शीट भरते समय कुछ चूक की थी, फिर भी उन्हें चयन प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर नहीं किया जाना चाहिए था। ओएमआर शीट में गोलों को चिह्नित/गहरा करने के निर्देशों और ओएमआर शीट के साथ-साथ विज्ञापन में निहित निर्देशों का हवाला देते हुए, यह निवेदन किया गया है कि इस आशय की कोई विशिष्ट घोषणा नहीं दी गई है कि यदि उचित रूप से गहरा नहीं किया गया है या गहरा नहीं किया गया है, तो इसका परिणाम अनिवार्य रूप से उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से बाहर करने में होगा। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि ऐसे मामलों में यदि मूल्यांकन के लिए ओएमआर शीट को प्रणाली द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, तो याचिकाकर्ताओं को उचित सुधार

करके, भरे हुए गोलों को भरकर या सुधारकर ओएमआर शीट को सही करने का एक अवसर दिया जाना चाहिए था। आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता मेधावी हैं और यदि उन्हें ऐसी चूक के आधार पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है, तो यह उनकी भविष्य की व्यावसायिक संभावनाएं को प्रभावित कर सकता है।

3. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम प्रति पर इस न्यायालय का ध्यान यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स बनाम जगदीश चंद्र जाट के मामले में डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या **12323/2020** में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **19.08.2021** को पारित एक आदेश की ओर आकर्षित किया।

4. स्वीकार्य रूप से, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला भरने के लिए चिह्नित स्थान को नहीं भरा और खाली छोड़ दिया। याचिकाकर्ता संख्या 2 ने प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला से संबंधित गोले को गहरा नहीं किया।

5. चूंकि ओएमआर शीट के मूल्यांकन की परीक्षा प्रणाली मशीनों द्वारा प्रणाली-आधारित मूल्यांकन तंत्र पर आधारित है, इसलिए प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं सहित सभी उम्मीदवारों को ओएमआर शीट में चिह्नित/गहरा करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश और निर्देश जारी किए। इसका कारण यह है कि यदि ओएमआर शीट निर्देशों के अनुसार ठीक से नहीं भरी जाती है, तो उसे मशीनीकृत प्रणाली द्वारा कैप्चर और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ओएमआर

शीट में गोलों को चिह्नित/गहरा करने के निर्देशों के तहत, खंड 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ओएमआर शीट में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला (QPB-Question Paper Book) की श्रृंखला को भरते/गहरा करते समय, गलत तरीके से गहरा किया गया या गलत विधि से गहरा किया गया या कई गोलों को गहरा किया गया या गोले को गहरा नहीं किया गया या गोले पर स्याही फैल गई, तो मूल्यांकन प्रक्रिया बाधित हो सकती है। ओएमआर निर्देश उचित अंकन पर भी जोर देते हैं। यदि प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला को उचित अंकन और गोले को गहरा करके इंगित नहीं किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि ओएमआर शीट का प्रणाली में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से याचिकाकर्ताओं की ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ताओं को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।

6. सार्वजनिक रोजगार के तहत पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया की शुचिता को बनाए रखने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पूरी प्रक्रिया न केवल स्पष्ट रूप से निर्धारित हो बल्कि परीक्षा एजेंसी के साथ-साथ परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों द्वारा भी ईमानदारी से पालन की जाए। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए, उसे दिए गए विभिन्न निर्देशों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। किसी दिए गए मामले में निर्देशों का उल्लंघन मूल्यांकन प्रक्रिया और चयन प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। जहां प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला का उल्लेख नहीं किया गया है, वहां ओएमआर का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यदि किसी

उम्मीदवार द्वारा ऐसी गलती पहले ही की जा चुकी है, तो चयन प्रक्रिया में ऐसी कोई निर्धारित प्रणाली नहीं है जो ऐसे उम्मीदवारों को उस दोष को किसी विशेष तरीके से दूर करने की अनुमति दे।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं और अन्य उम्मीदवारों को, जिन्होंने ओएमआर शीट भरने में चूक की थी, उन्हें सही करके ऐसी चूक को दूर करने की प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए थी।

8. हमें डर है कि ऐसी व्यापक छूट परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। यह प्रस्ताव कि ओएमआर शीट जमा होने के बाद, इसे किसी मैनुअल प्रक्रिया द्वारा फिर से जांचा जाना चाहिए या जहां ओएमआर शीट को मूल्यांकन प्रणाली द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है, उसे उम्मीदवारों द्वारा सही करने की अनुमति दी जानी चाहिए, चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पटरी से उतार देगा और यह न केवल चयन की प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब करेगा बल्कि संदेह भी पैदा करेगा, क्योंकि इस तरह की प्रथा दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील है।

9. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य बनाम जगदीश चंद्र जाट (उपर्युक्त) के मामले में ओएमआर शीट भरने के संबंध में निर्देश का पालन न करने के समान मुद्दे का सामना किया और स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स बनाम जी. हेमलता एंड अन्य के मामले में सिविल अपील

संख्या **6669/2019** में **28.08.2019** को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए यह अवलोकन किया कि जारी किए गए निर्देश अनिवार्य हैं और उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि निर्देशों के नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन सर्वोच्च महत्व का है।

10. जी. हेमलता एंड अदर्स (उपर्युक्त) के मामले में परीक्षा के संचालन के लिए जारी निर्देशों की शुचिता और उनके उल्लंघन के परिणाम को उजागर करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में स्थापित करता है:-

"7. सुश्री वी. मोहना, प्रतिवादी के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार, एस.एल.पी. में कानून का कोई पर्याप्त प्रश्न नहीं है जो हमारे हस्तक्षेप को उचित ठहराना। उन्होंने निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा एक त्रुटि की गई थी जिसे उच्च न्यायालय ने सही ढंग से माफ कर दिया था। उन्होंने हमसे एक भावुक अपील की कि एक मेधावी पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के भविष्य को प्रारंभ में ही समाप्त कर देना नहीं चाहिए।

8. हमने प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए निवेदनों पर गंभीरता से विचार किया है। आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देश अनिवार्य हैं, कानून का बल रखते हैं और उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। निर्देशों के नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन सर्वोच्च महत्व का है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय आयोग द्वारा जारी निर्देशों को संशोधित/शिथिल नहीं कर सकता है¹।

9. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी की उत्तर पुस्तिका को तलब करने और उसका अवलोकन करने के बाद यह पाया कि निर्देशों का उल्लंघन हुआ था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मानवीय आधार पर सहानुभूतिपूर्ण विचार पर प्रतिवादी को राहत प्रदान की। प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में ताहेराखातून (डी) बाय एलआरएस बनाम सालंबिन मोहम्मद² और चंद्र सिंह एंड अदर्स बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अन्य³ में उद्धृत निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं कि हमें कानून के किसी भी पर्याप्त प्रश्न के अभाव में इस अपील का मनोरंजन नहीं करना चाहिए।

10. यह निष्कर्ष निकालने के बावजूद कि निर्देशों का पालन नहीं किया गया था, उच्च न्यायालय ने निर्देशों की अनिवार्य प्रकृति को अनदेखा करते हुए राहत प्रदान की। यह नहीं कहा जा सकता कि विवेक के ऐसे प्रयोग को हमारे द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए, खासकर जब ऐसा निर्देश उन निर्देशों के विपरीत हो जो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों पर बाध्यकारी हैं।

11. अपनी प्रेरक अपील में, सुश्री मोहना ने हमें अपील खारिज करने के लिए राजी करने की कोशिश की, जिससे प्रतिवादी को सिविल न्यायाधीश के पद के लिए चयन में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा सके। यह एक सुप्रसिद्ध कहावत है कि, कठिन मामले खराब कानून बनाते हैं। उमेश चंद्र शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में, वेंकटरमैया, जे. ने कहा कि: (एससीसी 735, पैरा 13)

"13.... संयम की ऐसी शक्ति का प्रयोग सार्वजनिक नियुक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया में अविश्वास की भावना पैदा करने की संभावना है जिसका उद्देश्य निष्पक्ष और तटस्थ होना है। इसके परिणामस्वरूप समानता के सिद्धांत का उल्लंघन भी हो सकता

है और मनमानी हो सकती है। उच्च न्यायालय द्वारा इंगित मामले निस्संदेह कठिन मामले हैं, लेकिन कठिन मामलों को खराब कानून बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इन परिस्थितियों में, हम नियमों की कठोर व्याख्या के पक्ष में हैं और मानते हैं कि उच्च न्यायालय के पास नियमों के तहत ऐसी कोई शक्ति नहीं थी।

12. रॉबर्ट्स, सी.जे. ने कैपरटन बनाम ए.टी. मैसी कोल कंपनी इंक में कहा कि: (एससीसी ऑनलाइन यूएस एससी) :

"अत्यधिक मामले अक्सर स्थापित कानूनी सिद्धांतों की सीमाओं का परीक्षण करना। कानूनी सिद्धांत का पालन करने के बजाय, अत्यधिक मामले को सही करने की इच्छा के आगे झुकना की एक कीमत होती है। वह कीमत इतनी बार प्रदर्शित हुई है कि इसे एक कानूनी सूक्ति में समाहित किया गया है:

"कठिन मामले खराब कानून बनाते हैं।"

13. गहन विचार करने के बाद, हमें डर है कि हम उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उम्मीदवार के पक्ष में कोई भी आदेश जिसने अनिवार्य निर्देशों का उल्लंघन किया है, खराब कानून स्थापित करेगा। सुश्री मोहना द्वारा किया गया दूसरा निवेदन कि हमारे द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत एक आदेश पारित किया जा सकता है जिसे एक नज़ीर के रूप में नहीं माना जाएगा, वह भी हमें आकर्षित करना नहीं है।"

11. उपर्युक्त कथन पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय की खंडपीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स बनाम जगदीश चंद्र जाट के मामले में यह माना कि उम्मीदवार द्वारा की गई ऐसी गलतियों को सही करने की अनुमति नहीं दी जा

सकती है और एकमात्र विकल्प ऐसे उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से बाहर करना है।

12. उपरोक्त विचार के आलोक में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की घोषणा और यहां ऊपर संदर्भित समान मामलों में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन करते हुए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार, खारिज की जाती है।

(आशुतोष कुमार), जे

(मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव), मुख्य न्यायमूर्ति

एन.गांधी-राहुल/7

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

MITALI KARWA, ADVOCATE
Office At-
O.N. 417, 4th Floor, Sunny Paradise, Tonk Road,
Jaipur- 302018
M:- (+91)9001197999
R/5754/2022